International Journal of Trend in Scientific Research and Development (IJTSRD)
Volume 6 Issue 3, March-April 2022 Available Online: www.ijtsrd.com e-ISSN: 2456 – 6470

शिरोमणि अकाली दल एवं पंजाब की राजनीति में भूमिका

Dr. Sukhwinder Singh

Assistant Professor, Department of Humanities & Social Sciences,
Govt. Engineering College, Jhalawar, Rajasthan, India

ABSTRACT

दिल्ली-हरियाणा बार्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में पंजाब सबसे बड़ा योगदान दे रहा है। पंजाब का प्रमुख राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल इस आंदोलन को अपने पक्ष में भुनाने की रणनीति तैयार कर रहा है। इसके लिए पार्टी के संरक्षक और पांच बार मुख्यमंत्री रह चुके प्रकाश सिंह बादल सक्रिय भूमिका में आ गए हैं।

पंजाब में पिछले विधानसभा चुनाव से अपना पंथक जनाधार खो चुका शिरोमणि अकाली दल (बादल) किसान आंदोलन को सिख संघर्ष का रूप देने के लिए फिर से राज्यों को अधिक अधिकार देने के पुराने एजेंडे पर चल पड़ा है। इन दिनों मोदी सरकार के खिलाफ पंथक वोट में आए उबाल को शिअद के पक्ष में मोड़ने की रणनीति के तहत ही पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने पद्म विभूषण लौटने की घोषणा की।

वहीं शिअद के सीनियर नेताओं को मोदी विरोधी नेताओं से मुलाकात करने के लिए भेजना, इस बात का संकेत है कि प्रकाश सिंह बादल विधान सभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में नए समीकरण बैठाने के लिए सक्रिय हो गए हैं।

कुछ दिन पहले शिअद के पूर्व सांसद प्रेम सिंह चंदूमाजरा और अन्य अकाली नेताओं ने एनडीए की पूर्व सहयोगी शिवसेना के मुखिया व महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का दरवाजा खटखटाकर किसानों के आंदोलन के लिए सहयोग मांगा। यह शिअद के राज्यों को अधिकार देने के अपने पुराने एजेंडे पर वापस लौटने के संकेत भी हैं। शिअद राज्यों को अधिक अधिकार देने के मुद्दे पर भाजपा विरोधी दलों को एक प्लेटफार्म में इकट्ठा कर मोदी सरकार के विरुद्ध नया मोर्चा शुरू करने की ताक में है।

How to cite this paper: Dr. Sukhwinder Singh "Shiromani Akali Dal and Role in Punjab Politics" Published in International Journal of Trend in Scientific Research and Development (ijtsrd), ISSN: 2456-6470, Volume-6 | Issue-3, April 2022, pp.1999-2004, URL: www.ijtsrd.com/papers/ijtsrd49891.pdf

IJTSRD49891

Copyright © 2022 by author (s) and International Journal of Trend in Scientific Research and Development Journal. This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution License (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0)

परिचय

शिअद की सियासत सदा केंद्र सरकार के विरोध के आसपास घूमती रही है। 1997 में पंजाब के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिलने और भाजपा के साथ हुए राजनीतिक समझौते के बाद अकाली दल के संघर्ष की धार सत्ता ने कुंद कर दी थी। लेकिन किसान संघर्ष ने शिअद को 23 वर्ष बाद एक बार फिर केंद्र से संघर्ष करने का मौका दिया है।

अपनी पंथक शक्ति गंवा चुके शिअद को हालांकि अब तक किसान संघर्ष का कोई भी सियासी लाभ नहीं मिला है। पंथक वोट बैंक में शामिल किसानों को अपने पाले में लाने के लिए बादल ने पद्म विभूषण वापस करने की घोषणा की, लेकिन इससे भी शिअद को कोई भी पंथक सहानुभूति नहीं मिली।[1]

शिअद अध्यक्ष सुखबीर बादल ने शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) अध्यक्ष बीबी जागीर कौर की पंथक छवि को शिअद के पक्ष में भुनाने के लिए कवायद शुरू की है। इसके तहत भारत बंद की कॉल को एसजीपीसी ने पूरा दिया और सचखंड श्री हरमंदिर साहिब के हजूरी रागी सिंहों ने भी किसान आंदोलन के समर्थन करने की घोषणा की। शिअद सिखों की धार्मिक शख्सियतों के माध्यम से इस आंदोलन को सिख संघर्ष के साथ जोड़ने की रणनीति पर काम करता दिख रहा है।[2]

गुरुद्वारों को महंतों के कब्जे से छुड़वाने और अंग्रेजों से देश को आजादी दिलाने के अहम भूमिका निभाने वाला शिरोमणि अकाली दल (Shiromani Akali Dal) देश का दूसरा ऐसा राजनीतिक दल बन गया है जिसने भारत में अपना 100 साल का राजनीतिक सफर पूरा कर लिया है. इससे पहले सिर्फ कांग्रेस (Congress) ही देश में ऐसी पार्टी है जिसने सौ साल से ज्यादा का राजनीतिक सफर पूरा किया है. शिरोमणि अकाली दल ने अपने इस सौ सालों के लंबे सफर में कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं. कई बार वैचारिक तौर पर इसमें बदलाव दिखे तो कई बार पार्टी को टूट का सामना भी करना पड़ा.

गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के सहयोग और सिखों की आवाज बनकर समुदाय के मुद्दे सरगर्मी से उभारने के लिए अकाली दल की स्थापना 14 दिसंबर 1920 को को हुई थी. सरमुख सिंह झबाल शिअद के पहले प्रधान थे. उस समय देश अंग्रेजों का गुलाम था. 7 जुलाई 1925 को गुरुद्वारा बिल लागू होने के बाद अकाली दल आजादी की लड़ाई में शामिल हो गया. दरअसल 1925 में गुरुद्वारा एक्ट बनाकर सभी ऐतिहासिक गुरुद्वारों का रखरखाव शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को दे दिया गया. महात्मा गांधी ने इस जीत को आजादी की लड़ाई की पहली जीत बताया था.[3,4]

विचार-विमर्श

1920 में जब इस पार्टी की स्थापना की गई तो इसे पंथक हितों की लड़ाई लड़ने वाली पार्टी माना जाता था. 1996 में मोगा कांफ्रेंस में इसमें कुछ बदलावों को लेकर चर्चा हुई. पार्टी ने अपनी पुरानी छवि से बाहर निकलने के लिए विचार किया. इस कांफ्रेंस में पार्टी ने सैद्धांतिक तौर पर बड़ा बदलाव करते हुए शिरोमणि अकाली दल को पंथक पार्टी से सेकुलर पार्टी के रूप में बदल लिया. पार्टी के इतिहास के हिसाब से यह सबसे बड़ा बदलाव था. दरअसल 1978 से लेकर 1995 तक पंजाब में अगर किसी चीज की सबसे बड़ी कमी देखी गई तो वह हिंदू और सिखों के बीच आपसी सौहार्द था. पहले इमरजेंसी, बाद में 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार और इंदिरा गांधी की मौत के बाद सिख कत्लेआम. दोनों ही घटनाओं ने आपसी द्वेष का काफी बढ़ाया.

1920 में पार्टी की स्थापना के बाद अकाली दल ने अपना सियासी सफर 1937 में शुरु किया. प्रोविंशियल चुनाव में शिअद ने 10 सीटें जीत ताकत अहसास कराया था. 1992 तक बीजेपी और अकाली दल अलग-अलग चुनाव लड़ती थी. इसके बाद दोनों ने साथ आने का फैसला लिया. 1996 में अकाली दल ने 'मोगा डेक्लरेशन' पर साइन किया और 1997 में बीजेपी के साथ पहली बार चुनाव लड़ा. दोनों अकाली दल और बीजेपी की दोस्ती लगातार चलती रही लेकिन किसान आंदोलन के बाद अकाली दल मोदी कैबिनेट से बाहर हो गया. यहां यह भी गौर करने वाली बात है कि पंजाब में अकाली दल एकमात्र ऐली पार्टी है जिसने लगातार दो बार चुनाव जीता है. हालांकि 2017 के चुनाव में पार्टी की बड़ी हार हुई. पार्टी ने 117 सीटों पर चुनाव लड़ा लेकिन 15 सीटों पर ही सिमट गई. पार्टी को इतनी भी सीटें नहीं मिली कि वह विपक्षी दल का तमगा अपने पास रख सके.[5,6]

परिणाम

पंजाब की राजनीति के भीष्म पितामह कहे जाने वाले और शिरोमणि अकाली दल(शिअद) प्रमुख प्रकाश सिंह बादल को राजनीति में सात दशकों से भी अधिक का समय हो गया है और अभी 94 वर्ष की आयु में वह पार्टी को जीत की राह पर ले जाने के लिए तैयार हैं। पंजाब की राजनीति में पिछले कुछ वर्षों से हुई उथल पुथल के बावजूद वह राजनीतिक क्षेत्र में एक उदारवादी नेता के तौर पर जाने जाते रहे हैं और एक बार फिर वह जनता के नेता होने के अपने करिश्मे को दिखाने की कोशिश में है। वह राज्य की सक्रिय राजनीति में पिछले पांच दशकों से हैं और 1970 में देश का सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी उन्हें ही हासिल है।[7,8]

राजनीतिक क्षेत्र में बादल सीनियर के नाम से भी विख्यात प्रकाश सिंह बादल 1947 में मात्र 20 वर्ष की आयु में देश के सबसे युवा सरपंच बने थे और इतने वर्षो तक राजनीतिक बिसात खेलने के बाद उन्होंने वर्ष 2008 में पार्टी की कमान अपने एकमात्र पुत्र सुखबीर सिंह बादल को सौंप दी थी। प्रकाश सिंह बादल राजनीति की रग रग से वाकिफ है और वह बेहतर चुनावी प्रबंधन के गुर भी जानते हैं। संसद और विधानसभा में 11 बार अपनी पारी खेलने वाले बादल सीनियर एक बार फिर राज्य की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं।

पंजाब विधानसभा चुनावों की घोषणा से कुछ हफ्तों पहले ही उन्होंने मुक्तसर जिले में अपने लांबी विधानसभा क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया है। इस दौरान वह अपनी पुत्रवधू और बठिंडा से सांसद हरसिमरत कौर को अपने साथ नियमित तौर पर लोगों के साथ संवाद करने के लिए ले जाते हैं। वह तकनीक का अधिक इस्तेमाल करने के बजाए लोगों के साथ आमने सामने संवाद करना अधिक पसंद करते हैं।[9,10]

अभी हाल ही में एक जनसभा के दौरान पूर्व केन्द्रीय मंत्री हरसिमरत कौर ने कहा था जब राज्य में शिअद और बहुजन समाज पार्टी की सरकार सत्ता में आएगी तो सुखबीर बादल आपके मुख्यमंत्री होंगे और बादल साहब आपके सुपर मुख्यमंत्री होंगे। आपको उन्हें चुनाव लड़ने के लिए मनाना है क्योंकि वह कह रहे हैं कि सेहत उनका साथ नहीं दे रही है लेकिन आप सभी को उन्हें इस बात के लिए मनाना है और अगर वह घर बैठ कर भी चुनाव लड़ते हैं तो आप उन्हें जिता सकते हैं। हालांकि बादल सीनियर ने कई बार अपने भाषणों में कहा है कि पार्टी जो भी जिम्मेदारी उन्हें सौंपेगी ,वह उसे पूरा करेंगे।

अभी हाल में पार्टी नेता और पूर्व मंत्री बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ मादक पदार्थ केस में मामला दर्ज होने के बाद कड़ी प्रतिक्रिया करते हुए बादल सीनियर ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा था कि वह अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बदले की राजनीति का सहारा नहीं ले। उन्होंने 23 दिसंबर को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा था कि बेअदबी की घटना से प्रत्येक धर्मनिष्ठ सिख की भावना आहत होती है और हाल ही की हिंसा तथा बेअदबी की घटनाओं का वर्ष 2022 के पंजाब विधानसभा चुनावों के नतीजों से सीधा संबंध है।

उन्होंने कहा कि श्री हरमंदर साहिब को मुगलों, ब्रिटिशों और कांग्रेस शासकों ने अपने कुटिल तथा खतरनाक मंसूबों से निशाना बनाया था। उन्होंने कहा वर्ष 1984 के बाद यह पहली बार है कि मानवता के सबसे पवित्र स्थान को नापाक मंसूबों के चलते निशाना बनाया गया है और यह कोई महज संयोग नहीं है कि कांग्रेस के शासन में ऐसा हुआ है। बादल सीनियर ने विभिन्न अकाली आंदोलनों के दौरान लगभग 17 वर्ष जेलों में बिताए हैं और इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें नेल्सन मंडेला तक कह दिया है।

प्रकाश सिंह बादल का कहना है मेरे विरोधियों ने मेरे तथा परिवार के खिलाफ सैंकड़ों मामले दर्ज कराए हैं लेकिन मैं इनकी परवाह नहीं करता हूं। मैंने विभिन्न अकाली आंदोलनों में अपने जीवन के 17 वर्ष जेल में बिताए हैं और मैं एक बार जेल जाने से नहीं डरता हूं। कांग्रेस सरकार ने मेरी पत्नी को भी नहीं बख्शा था और अगर वे सोचते है कि ऐसा कर अकाली दल को कमजोर कर देंगे तो यह उनकी गलतफहमी है । राजनीतिक जीवन में बेहद चुतर और जमीन से जुड़े बादल सीनियर ने इस हफ्ते एक और वरिष्ठ अकाली नेता रणजीत सिंह ब्रह्मपुरा को पार्टी में लाने में अहम भूमिका निभाई है। उनका कहना है आज मैं बहुत खुश हूं कि एक बार फिर दो भाइयों ने हाथ मिलाए हैं।

उन्होंने अकाली दल से गए अन्य नेताओं से भी पार्टी में वापसी की अपील करते हुए कहाजब भी हम पर हमला हुआ , हम और मजबूत होकर उभरे हैं और इंदिरा गांधी भी हमारी इच्छा शक्ति को नहीं तोड़ पाई थीं। कांग्रेस की तरफ से हमारे खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराए जा रहे हैं और उनके यह काम भी हमें हमारे मकसद को हासिल करने से नहीं डिगा पाएंगे। उन्होंने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के राज में सुशासन की अनदेखी की गई है और लोगों के कल्याण तथा विकास संबंधित सभी योजनाओं को रोक दिया गया है और यही सब इस सरकार की पराजय के कारण बनेंगे।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बार विधानसभा चुनावों में राज्य में मादक पदार्थ की समस्या और हाल ही में बेअदबी की घटनाओं के बाद हिंसा के मामले सबसे बड़े मुद्दों के रूप में होंगे। पार्टी ने हालांकि लांबी विधानसभा सीट से कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है लेकिन पार्टी प्रमुख सुखबीर सिंह बादल ने आगामी विधानसभा चुनावों के लिए 91 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है और यह भी कहा है कि उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेगी। राज्य की 117 सदस्यीय विधानसभा सीटों के लिए शिअद 97 और बसपा 20 सीटों पर चुनाव मैंदान में अपनी किस्मत आजमाएगी।

गौरतलब है कि शिअद और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का दो दशकों से भी अधिक पुराना संबंध था लेकिन केन्द्र सरकार के तीन विवादित कृषि कानूनों को लेकर हुए तीव्र मतभेद के बाद शिअद ने राजग से सितंबर 2020 में नाता तोड़ लिया था। अकाली दल के एक वरिष्ठ नेता ने आईएएनएस को बताया चूंकि सुखबीर सिंह बादल के पास अपने पिता जैसी राजनीतिक समझ नहीं है और आगामी विधानसभा चुनाव में उसक सामने करो या मरो की स्थिति है जिसे देखते हुए वह पार्टी को पुनर्जीवित करने के लिए बादल सीनियर पर ही निर्भर है। कांग्रेस पार्टी को पंजाब में लगभग एक दशक के बाद राजनीति में आने का मौका मिला था और चार फरवरी 2017 को हुए विधानसभा चुनावों में उसे 77 सीटें मिली थीं। इससे पहले 2007-17 तक राज्य में अकाली दल-भाजपा गठबंधन सत्ता में रहा था।

निष्कर्ष

शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष और फिरोज़पुर से लोकसभा सांसद सुखबीर सिंह बादल ने अपने ट्विटर पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की चिट्ठी हाथ में लिए एक फ़ोटो पोस्ट की.

साथ में ट्वीट में लिखा, केंद्रीय कृषि मंत्री ने आधिकारिक तौर पर चिट्ठी लिख कर हमें आश्वस्त किया है कि किसानों से जुड़े तीनों अध्यादेश का सरकारी एजेंसियों की ओर से फ़सलों की ख़रीद पर कोई फ़र्क़ नहीं पड़ेगा. उन्हें अपनी फ़सलों का उचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) मिलेगा.

केंद्रीय मंत्रिमंडल से उनकी पत्नी और खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने अध्यादेश को किसान विरोधी बताते हुए इस्तीफ़ा दे दिया.

सुखबीर सिंह बादल ने लोकसभा में कहा, "हम इन अध्यादेशों का विरोध करते हैं क्योंकि 20 लाख किसान, 3 लाख मंडी में काम करने वाले मज़दूर, 30 लाख खेत में काम करने वाले मज़दूर और 30 हज़ार आढ़तियों के लिए ये ख़तरे की घंटी है. पंजाब की पिछली 50 साल की बनी बनाई किसान की फ़सल ख़रीद व्यवस्था को ये चौपट कर देगी."

20 दिनों में ऐसा क्या हुआ, जिससे 20 साल से भी ज़्यादा पुरानी दोस्ती में दरार आ गई.

क्या ख़ुद को किसानों की पार्टी कहने वाली अकाली दल 20 दिन पहले तक अध्यादेश से किसानों को होने वाली दिक़्क़तों से वाक़िफ़ नहीं थी?

यही सवाल हमने शिरोमणि अकाली दल के राज्यसभा सांसद नरेश गुजराल से पूछा.[11,12]

बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, "कैबिनेट में जिस दिन ये पास किया गया, हमारी पार्टी ने उस वक़्त भी इसका विरोध किया था. केंद्र सरकार कह रही है कि ये बिल किसानों के हित में है, हमने केंद्र सरकार के पक्ष को किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान सरकार की बात मानने को तैयार ही नहीं है. दोनों के बीच में, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा 'कम्यूनिकेशन गैप' 'ट्रस्ट गैप' है. जब हमें अहसास हो गया कि हमारे किसान इस बिल को स्वीकार नहीं करना चाहते हैं और हम किसानों की पार्टी हैं, हम उन्हीं का प्रतिनिधित्व करते हैं. तो हमने उनकी बात को समझ लिया, और हमें ये सख़्त क़दम उठाना पड़ा."[12]

संदर्भ

[1] Banga, Indu (2017). Jacobsen, Knut A.; et al. (eds.). Brill's Encyclopedia of Sikhism. Brill Academic. ISBN 978-90-04-29745-6.

[2] Dilgeer, Harjinder Singh (1997), The Sikh Reference Book; Sikh University Press / Singh Brothers Amritsar, 1997.

[3] Dilgeer, Harjinder Singh (2005), Dictionary of Sikh Philosophy; Sikh University Press / Singh Brothers Amritsar, 2005.

[4] Dilgeer, Harjinder Singh (2008), Sikh Twareekh; Sikh University Press / Singh Brothers Amritsar, 2008.

[5] Dilgeer, Harjinder Singh (2012), Sikh History (in 10 volumes); Sikh University Press / Singh Brothers Amritsar, 2010–2012.

[6] Duggal, Kartar Singh (1988). Philosophy and Faith of Sikhism. Himalayan Institute Press. ISBN 978-0-89389-109-1.

[7] Kaur, Surjit; Amongst the Sikhs: Reaching for the Stars; New Delhi: Roli Books, 2003, ISBN 81-7436-267-3

[8] Khalsa, Guru Fatha Singh; Five Paragons of Peace: Magic and Magnificence in the Guru's Way, Toronto: Monkey Minds Press, 2010, ISBN 0-9682658-2-0, GuruFathaSingh.com

[9] Khalsa, Shanti Kaur; The History of Sikh Dharma of the Western Hemisphere; Espanola, New Mexico, US: Sikh Dharma; 1995 ISBN 0-9639847-4-8

[10] Singh, Khushwant (2006). The Illustrated History of the Sikhs. Oxford University Press. ISBN 978-0-19-567747-8.

[11] Singh, Patwant (1999). The Sikhs. Random House. ISBN 978-0-385-50206-1.

[12] Takhar, Opinderjit Kaur, Sikh Identity: An Exploration of Groups Among Sikhs. Burlington, Vermont: Ashgate; 2005 ISBN 0-7546-5202-5